



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 अग्रहायण 1938 (श10)  
(सं० पटना 1010) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

---

सं० 08/आरोप-01-69/2014-13302सा०प्र०  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 सितम्बर 2016

श्री भानु प्रताप सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5468, दिनांक 27.08.2013 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' पुनर्गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-1349, दिनांक 23.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री सिंह के वार्धक्य सेवानिवृत्त (दिनांक 31.08.2015) हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक-3740, दिनांक 11.03.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पूरित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी यथा, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1410, दिनांक 08.05.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों में से आरोप सं० 01 एवं 05 को आंशिक रूप से प्रमाणित, आरोप सं०-02 एवं 03 को प्रमाणित तथा आरोप सं० 04 को अप्रमाणित बताया गया।

3. विभागीय पत्रांक-7772, दिनांक 28.05.2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री सिंह से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह ने स्पष्टीकरण (पत्रांक-111 मु०, दिनांक 27.07.2015) समर्पित करते हुए प्रमाणित आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत किया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों पर उनके लिखित अभिकथन में वर्णित तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। इसके साथ ही चावल की बड़ी मात्रा व्ययगत होने से निगम को हुए मार्जिन मनी की क्षति के संबंध में उनका यह कथन कि "भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध भंडारण के अनुसार ही आर०ओ० निर्गत किया जाता था एवं आर०ओ० क्रय करने की मुख्य जिम्मेदारी सहायक लेखा पदाधिकारी की थी" को भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

क्योंकि भारतीय खाद्य निगम से चावल के उठाव में सम्भावित विलम्ब को देखते हुए अवधि विस्तार संबंधी कार्रवाई की जवाबदेही जिला प्रबंधक के रूप में उनकी थी। उनकी लापरवाही के कारण खाधान्न व्ययगत हुआ और निगम को मार्जिन मनी की क्षति हुई।

5. सम्यक् विचारोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत कटौती 03 (तीन) वर्षों के लिए करने संबंधी शास्ति विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-5602, दिनांक 21.04.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1689, दिनांक 06.09.2016 द्वारा विनिश्चित दंड पर सहमति संसूचित की गयी।

6. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत श्री भानु प्रताप सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-367/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :-

(क) पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत कटौती 03 (तीन) वर्षों के लिए।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1010-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>